



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04022020-215921
CG-DL-E-04022020-215921

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 29, 2020/माघ 9, 1941

No. 28]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 29, 2020/MAGHA 9, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2020

सं. 58 / 2015-2020

विषय: दिनांक 07.03.2019 से परिधान एवं निर्मितियां क्षेत्र (आईटीसी एचएस 2017 का अध्याय 61, 62 और 63) की मदों हेतु एमईआईएस की समाप्ति, प्रक्रिया पुस्तक, 2015-20 के पैरा 4.95 में संशोधन और आरओएससीटीएल स्कीम के कार्यान्वयन हेतु एएनएफ 4द में संशोधन।

फा. सं. 01/61/180/360/एम-19/पीसी-3/भाग-2-विदेश व्यापार नीति (2015-2020) के पैरा 1.03 और 3.13(क) एवं (ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

1. एमईआईएस हेतु प्रयोज्य प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी) के परिशिष्ट 3ख, तालिका-2 में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है:-

“दिनांक 07.03.2019 से किए गए निर्यात हेतु आईटीसी एचएस 2017 के अध्याय 61, 62 और 63 (परिधान एवं निर्मितियों) के अन्तर्गत मदों हेतु कोई एमईआईएस लाभ उपलब्ध नहीं होगा”।

2. प्रक्रिया पुस्तक के संशोधित पैरा 4.95 और 4.96 निम्नानुसार हैं:

4.95 राज्य और केन्द्रीय लेवी और करों में छूट देने हेतु स्कीम (आरओएससीटीएल) और आरओएससीटीएल के अंतर्गत अतिरिक्त तदर्थ प्रोत्साहन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया।

क. विदेश व्यापार नीति का पैरा 4.01 (ग) आरओएससीटीएल के बारे में है। आरओएससीटीएल स्कीम और आरओएससीटीएल के तहत अतिरिक्त तदर्थ प्रोत्साहन पर विवरण हेतु वस्त्र मंत्रालय की समय-समय पर जारी की गई राजपत्र अधिसूचनाओं को देखा जा सकता है।

- ख. आरओएससीटीएल के तहत छूट के दावे और अतिरिक्त तदर्थ प्रोत्साहन हेतु आवेदन एएनएफ 4 में संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग करते हुए डीजीएफटी की वेबसाइट <http://dgft.gov.in> पर ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा। संबंधित शिपिंग बिलों को निर्यातक/ आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ ऑनलाइन लिंक किया जाएगा। आरओएससीटीएल हेतु आवेदन करने के लिए ई-बीआरसी को लिंक करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ऑनलाइन मॉड्यूल में निर्यातक द्वारा एक एकल आवेदन में अधिकतम 50 शिपिंग बिलों को जोड़ना अनुमत होगा।
- ग. दिनांक 07.03.2019 से 31.12.2019 की अवधि में मान्य निर्यात तारीख वाले और दिनांक 01.01.2020 को या इसके बाद मान्य निर्यात तारीख वाले शिपिंग बिलों के लिए आरओएससीटीएल के अंतर्गत दावों के लिए अलग ऑनलाइन आवेदनों को प्रस्तुत किया जाएगा।
- घ. स्प्लिट स्क्रिप्स की सुविधा: प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 3.09 के प्रावधान यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।
- ड. आरओएससीटीएल के आवेदन हेतु क्षेत्राधिकार प्राप्त क्षेत्रीय प्राधिकारी प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 3.06 (ख) के अनुसार होगा। आवेदक सुनिश्चित करेंगे कि वे स्क्रिप प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 3.06 (ख) के अनुसार क्षेत्राधिकार के संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को ही आवेदन कर रहे हैं तथा स्क्रिप हेतु ऑनलाइन आवेदन करते समय इस संबंध में घोषणा प्रस्तुत करेंगे। तथापि वित्तीय वर्ष की शुरुआत में क्षेत्रीय प्राधिकारी को चुनने तथा उस वित्तीय वर्ष में सभी आवेदनों हेतु उसी क्षेत्रीय प्राधिकारी को बनाए रखने संबंधी पैरा 3.06 (क) में लगाई गई पाबंदी लागू नहीं होगी।
- च. आरओएससीटीएल स्क्रिप के लिए पंजीकरण के पत्तन का चयन: ऑनलाइन आवेदन करते समय
- ईडीआई पत्तनों और गैर-ईडीआई पत्तनों से शिपमेंट को एक आवेदन में क्लब नहीं किया जा सकता है।
 - आवेदक जहां से निर्यात किया जाता है ऐसे पत्तनों में से किसी एक पत्तन से ईडीआई समर्थित पत्तनों हेतु पंजीकरण के पत्तन का चयन कर सकता है।
 - गैर-ईडीआई पत्तन के माध्यम से निर्यात के मामले में, पंजीकरण का पत्तन निर्यात का संगत गैर-ईडीआई पत्तन होगा। तदनुसार, प्रत्येक गैर-ईडीआई पत्तन हेतु अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।
- छ) दिनांक 07.03.2019 से 31.12.2019 की अवधि में आवेदनों हेतु डीजीएफटी ऑनलाइन प्रणाली अतिरिक्त तदर्थ प्रोत्साहन राशि सहित प्रति शिपिंग बिल के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप से पात्रता को भरेगी तथा जहां भी एमईआईएस का लाभ दिया गया है उसे कम/समायोजित करेगी।
- ज) अंतिम पात्रता के प्रणाली आधारित अनुमोदन के पश्चात क्षेत्रीय प्राधिकारियों द्वारा कागज रहित तरीके से स्क्रिप जारी की जाएगी। तथापि, जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) के अंतर्गत क्षेत्रीय प्राधिकारी जारी किए गए 2 प्रतिशत आरओएससीटीएल आवेदनों की प्रति सप्ताह जांच करेंगे। डीजीएफटी प्रणाली द्वारा आरएमएस मामलों को यादृच्छिक रूप से ऑनलाइन जनरेट किया जाएगा।
- झ. स्क्रिप्स का पंजीकरण: आरओएससीटीएल के तहत जारी किए गए स्क्रिप्स के पंजीकरण का पत्तन निम्नानुसार होगा:
- शुल्क क्रेडिट स्क्रिप (स्प्लिट सहित) पंजीकरण के एकल पत्तन के साथ जारी किया जाएगा जो ईडीआई पत्तनों में से कोई भी एक हो सकता है जहां से निर्यात किया जाता है। गैर ईडीआई पत्तनों से शिपमेंट के मामले में, आरओएससीटीएल के तहत शुल्क क्रेडिट स्क्रिप (स्प्लिट सहित) पंजीकरण के एकल पत्तन के साथ जारी किया जाएगा जो निर्यात का पत्तन होगा।
 - शुल्क क्रेडिट स्क्रिप को स्क्रिप पर उल्लिखित पत्तन पर पंजीकृत कराने की आवश्यकता है। यह शुल्क क्रेडिट के उपयोग की अनुमति देने से पहले किया जाना है। एक बार ईडीआई पत्तन पर पंजीकृत हो जाने पर स्क्रिप का स्वचालित रूप से आयात हेतु किसी भी ईडीआई पत्तन पर और टेलीग्राफिक रिलीज एडवाइस (टीआरए) प्रक्रिया के तहत किसी भी मैनुअल पत्तन पर उपयोग किया जा सकता है।
 - यदि पंजीकरण का पत्तन मैनुअल पत्तन है, तो किसी अन्य पत्तन पर आयात हेतु टीआरए की आवश्यकता होगी।
- ञ. वैधता अवधि और पुनर्वैधीकरण: शुल्क क्रेडिट स्क्रिप जारी होने की तिथि से 24 महीनों की अवधि के लिए वैध होगा और उस तिथि पर वैध होगा जिस तिथि पर शुल्क का वास्तविक डेबिट किया जाता है। शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का पुनर्वैधीकरण अनुमत नहीं होगा जब तक कि इसे प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.20(ग) के तहत कवर न किया गया हो।
- ट. शुल्क क्रेडिट स्क्रिप हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि: शिपिंग बिल हेतु आवेदन।
- दिनांक 07.03.2019 से 31.12.2019 तक मान्य निर्यात आदेश की तिथि के साथ शिपिंग बिलों हेतु ऑनलाइन दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30.06.2020 होगी।
 - 01.01.2020 को अथवा उसके बाद मान्य निर्यात आदेश की तिथि के साथ शिपिंग बिलों हेतु ऑनलाइन आवेदनों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि मान्य निर्यात आदेश की तिथि से एक वर्ष के अन्दर होगी।

इन अंतिम तिथियों के बाद कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है तथा शिपिंग बिल कालातीत होंगे। आरओएससीटीएल स्कीम के तहत विलंब कटौती का कोई प्रावधान नहीं है।

ठ. आरए में गैर ईडीआई शिपिंग बिलों की प्रोसेसिंग करना: गैर ईडीआई शिपिंग बिलों के मामले में संबंधित आरए स्क्रिप प्रदान करने से पहले मूल शिपिंग बिल से निर्यातक द्वारा भरे गए विवरण को सत्यापित करेगा।

ड. प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के पैरा 2.24 के प्रावधानों के अंतर्गत आरओएससीटीएल के तहत डूप्लीकेट स्क्रिप जारी किया जा सकता है।

ढ. उन इकाइयों/आईईसी जो डीजीएफटी की अस्वीकृत इकाई सूची में हैं, को छोड़कर सभी निर्यातक आरओएससीटीएल के अंतर्गत दावा करने के लिए पात्र हैं।

4.96 वसूली तंत्र

क) आवेदक को निर्यात से संबंधित शिपिंग बिलों और अन्य दस्तावेजों का अभिलेख निर्गम के पश्चात जांच और वसूली प्रयोजनों के लिए स्क्रिप जारी होने की तारीख से 3 वर्षों की अवधि के लिए संभाल कर रखना है। लाइसेन्सिंग प्राधिकारी तीन वर्षों के भीतर किसी भी समय इन मूल दस्तावेजों की मांग कर सकता है। यदि आवेदक लाइसेन्सिंग प्राधिकारी द्वारा मांगे गए मूल दस्तावेज को प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो आवेदक को प्रदान की गई छूट स्क्रिप जारी होने की तारीख से सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 28 क के तहत निर्धारित दर पर ब्याज के साथ लौटाना होगा।

ख) साथ ही, ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहां निर्यातक के आवेदन के आधार पर एमईआईएस या अन्यथा के लिए समायोजित करते समय आरओएससीटीएल के अंतर्गत पात्र राशि से अधिक राशि जारी की गई है। ऐसे मामलों में संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी संगत स्क्रिप के इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड की जांच करेगा और यदि क्षेत्रीय प्राधिकारी को अत्यधिक दावा/अत्यधिक संवितरण का पता चलता है तो आवेदक विदेश व्यापार नीति के पैरा 3.19 में यथा विहित ब्याज के साथ अत्यधिक दावा का रिफंड करेगा।

ग) यदि आवेदक उपरोक्त यथा निर्धारित अत्यधिक दावा रिफंड नहीं करता है या क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा भेजे गए इससे संबंधित पत्र का 30 दिनों के भीतर जबाब नहीं देता है तो क्षेत्रीय प्राधिकारी एफटी (डी एवं आर) अधिनियम और नियमावली के अनुसार कार्रवाई आरंभ करेगा।

घ) अनुमत छूट विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत अनुमत समय के भीतर बिक्री से लाभ की प्राप्ति के अधीन है जिसके न होने पर ऐसी छूट को कभी-भी अनुमत नहीं होने के रूप में माना जाएगा। गलत या अधिक आरओएससीटीएल भुगतान की चुकौती के लिए क्षेत्रीय प्राधिकारियों द्वारा एफटी (डी एवं आर) अधिनियम, 1992 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा, निर्यात की गलत गणना से उत्पन्न स्क्रिपों के माध्यम से जारी छूट के किसी अत्यधिक भुगतान को लौटाना आवश्यक है। जहां-जहां इस तरह के अतिरिक्त भुगतान की वसूली बकाया है वहाँ निर्यातक द्वारा स्क्रिप के डेबिट होने की तारीख से पुनर्भुगतान की तारीख तक परिकलित 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भी भुगतान किया जाएगा। यदि निर्यातक अप्रयुक्त स्क्रिप वापस कर देता है तो कोई ब्याज नहीं लगाया जाएगा, तथापि, गलत घोषणा या कपटपूर्ण व्यवहार के आधार पर न्यायनिर्णय के आदेश के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है।

3. एनएनएफ 4द का संशोधन किया जाता है, और यह सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक के रूप में है।

4. निम्नलिखित पैरा को प्रक्रिया पुस्तक के अध्याय 3 में जोड़ा जाता है।

“3.01(1) परिधान और निर्मितियों (अध्याय 61, 62 और 63) के संबंध में 07.03.2019 से 31.12.2019 की अवधि के बीच मान्य निर्यात की तारीख सहित निर्यात के लिए एमईआईएस के तहत निर्यातकों को भुगतान किए गए अतिरिक्त अनुचित दावों को यथोचित रूप से जहां भी देय हो आरओएससीटीएल और वसूलियों के मद्दे समायोजित किया जाएगा।”

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: राज्य और केन्द्रीय कर और लेवी की छूट (आरओएससीटीएल) हेतु स्कीम के लिए वस्त्र मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं के आधार पर पैरा 4.95 और 4.96 में प्रक्रिया को संशोधित किया गया है और आयात-निर्यात प्रपत्र (एनएनएफ 4द) को संशोधित किया गया है। आरओएससीटीएल प्रारंभ करने के कारण दिनांक 07.03.2019 से किए गए निर्यात हेतु परिधान और निर्मितियां क्षेत्रों (अध्याय 61, 62, 63) की मर्दों के लिए एमईआईएस को वापस ले लिया गया है।

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

सार्वजनिक सूचना सं. दिनांक जनवरी, 2020 का अनुलग्नक

एनएनएफ— 4द

राज्य और केन्द्रीय करों और लेवी की छूट (आरओएससीटीएल) की योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदन प्रपत्र जैसा कि प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के पैरा 4.95 और 4.96 में अधिसूचित है।

आवेदकों के लिए दिशा निर्देश

1. आवेदन करने से पूर्व कृपया एचबीपी 2015-20 के पैरा 4.95 और 4.96 और आरओएससीटीएल पर वस्त्र मंत्रालय द्वारा प्रकाशित राजपत्र अधिसूचना और एएनएफ 4द घोषणाएं देख लें।
2. कृपया ध्यान दें कि 07.03.2019 से 31.12.2019 तक की अवधि के शिपिंग बिल और 01.01.2020 से शिपिंग बिल प्रस्तुत करने के लिए मान्य निर्यात तिथि के आधार पर अलग-अलग आवेदन किए जाने की आवश्यकता है।
3. 07.03.2019 से 31.12.2019 की अवधि के शिपिंग बिलों के लिए पहले से ही जारी, एमईआईएस के लिए उपयुक्त समायोजन के पश्चात समय-समय पर यथा संशोधित वस्त्र मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचनाओं के द्वारा अधिसूचित दरों अधिकतम सीमा/अतिरिक्त तदर्थ प्रोत्साहन के आधार पर ऑनलाइन ई कॉम मॉड्यूल स्वतः आरओएससीटीएल पात्रता की गणना कर लेगा।
4. आवेदक एक समय पर एक शिपिंग बिल का चयन/विवरण भरें। एक आवेदन में छूट के लिए अधिकतम 50 शिपिंग बिलों का चयन किया जा सकता है।

भाग क

1.	आवेदक का विवरण:										
i	आईईसी सं.										
ii	आईईसी का नाम										
iii	पता										
iv	दूरभाष सं.										
v	वैध/सक्रिय ई-मेल आईडी										

भाग ख**2. आवेदन का विवरण :**

- i. निर्यात लाइसेंसिंग वर्ष [कृपया मान्य निर्यात तिथि (एचबीपी का पैरा 9.12)] के आधार पर जिस वर्ष निर्यात किया गया है, उसका उल्लेख करें :
 - ii. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि :
 - iii. इस आवेदन के लिए निर्यात का पत्तन:
3. शिपिंग बिल विवरण: पात्र शिपिंग बिल ऑनलाइन शिपिंग बिल भंडार में उपलब्ध होंगे। निर्यातकों को शिपिंग बिलों का चयन करने और अपना आवेदन करने की आवश्यकता है। ईडीआई शिपिंग बिलों का विवरण भरने की आवश्यकता नहीं है।
4. अपेक्षित स्प्लिट प्रमाण पत्रों की सं. (प्रत्येक 5 लाख के गुणकों में):
5. आयात उद्देश्य के लिए पंजीकरण का पत्तन (पंजीकरण का पत्तन निर्यात किए जाने वालों पत्तनों में से एक होना चाहिए)।
6. घोषणा/वचनबद्धता

1	<p>मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि:</p> <p>क. कंपनी जिसके लिए आवेदन किया गया है, को निम्नलिखित किसी भी अधिनियम (समय-समय पर यथा संशोधित) के अधीन दण्डित नहीं किया गया/दंडित किया गया है (जो लागू है उसे चुनें)</p> <p>(i) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962</p> <p>(ii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944</p> <p>(iii) विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 और</p> <p>(iv) विदेशी मुद्रा अधिनियम, 1999</p> <p>(v) विदेशी मुद्रा संरक्षण, तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1974</p>
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>ख. कम्पनी/फर्म/एचयूएफ/न्यास (जैसा भी मामला हो) का कोई भी निदेशक/साझेदार/स्वामी/कर्ता/न्यासी/फर्म/एचयूएफ/न्यासी किसी अन्य कम्पनी/फर्म/संस्था जो डीजीएफटी की अस्वीकृत इकाई सूची (डीईएल) में है, का निदेशक/साझेदार/स्वामी/कर्ता/न्यासी नहीं है।</p> <p>ग. न तो कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय/फर्म के मुख्यालय और न ही उसके किसी शाखा कार्यालय(यों)/यूनिट(टों)/डिविजन(नों) को चूककर्ता घोषित किया गया है और न ही नीति के किसी प्रावधान के अधीन आयात/निर्यात करने के लिए अपात्र घोषित किया गया है।</p>
2	मैं/हम समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 उसके तहत बने नियमों और आदेशों, विदेश व्यापार नीति, प्रक्रिया पुस्तक और आयात निर्यात मद के आईटीसी (एसएच) वर्गीकरण के प्रावधानों के पालन की शपथ लेता हूँ/लेते हैं।
3	मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इस आवेदन में दिए गए ब्यौरे और विवरण मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया अथवा रोका नहीं गया है। मैं/हम पूर्णतः समझता हूँ/समझते हैं कि आवेदन में दी गई जानकारी गलत या झूठी साबित होगी तो मुझे/हमें कोई भी दण्डात्मक कार्रवाई अथवा परिणाम भुगताने पड़ सकते हैं जो कि विधि द्वारा निर्धारित या अन्यथा अपेक्षित हों।
4	मैंने एचबीपी 2015-20 के पैरा 3.06 (ख) को पढ़ लिया है और मैं परिशिष्ट 1 क के अनुसार अपने क्षेत्राधिकार प्राप्त क्षेत्रीय प्राधिकारी को आरओएससीटीएल आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ
5	मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैं विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.06 के अनुसार इस घोषणा को सत्यापित करने और हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हूँ
6	मैं एतद्वारा घोषित करता हूँ कि मैंने वसूली तंत्र से संबंधित एचबीपी 2015-20 के पैरा 4.96 के प्रावधानों को पढ़ा है और मैं घोषित करता हूँ कि इस आवेदन में दावे किए गए प्रेषित माल को बाद में वापस नहीं किया गया है। भविष्य में इसके वापस किए जाने के मामले में मैं सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के खंड 28ए के तहत निर्धारित ब्याज दरों के साथ दी गई छूट को वापस करने का वचन देता हूँ। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैंने राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से किसी अन्य तंत्र के तहत विनिर्दिष्ट लेवी और कर की ऋण/छूट/धन वापसी/प्रतिपूर्ति के लिए दावा नहीं किया है और दावा नहीं करूंगा।
7	मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन में इस संबंध में आरओएससीटीएल पर वस्त्र मंत्रालय के राजपत्र अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट प्रावधानों के उल्लंघन में कोई निर्यात शामिल नहीं है।
8	मैं सहमत हूँ कि दिनांक 07.03.2019 और 31.07.2019 के बीच निर्यात पोतलदान के लिए egazette.nic में उपलब्ध वस्त्र मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.01.2020 की फा. सं. 14/26/2016- आईटी/खंड II के अनुसार इस आवेदन में शिपिंग बिल के मद्दे दावा जहाँ भी लागू हो, इन निर्यात पोत लदानों पर पहले से ही लिए गए एमईआईएस लाभों के लिए उपयुक्त समायोजन के बाद प्रदान किया जाएगा।
9	यदि मुझे किसी अनुचित/अतिरिक्त आरओएससीटीएल राशि प्रदान की गई है तो मैं ऐसे स्क्रिप की तारीख से सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के खंड 28क के तहत निर्धारित दर पर ब्याज के साथ नकद में राशि वापस करने का वचन देता हूँ। यदि मैं आरओएससीटीएल के तहत संवितरित अतिरिक्त/अनुचित राशि वापस करने में असमर्थ होता हूँ या मैं संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष आरओएससीटीएल दावों की पुष्टि के लिए पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ होता हूँ तो मैं जानता हूँ कि एफटी (डीएंडआर) अधिनियम के तहत मैं दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी रहूंगा।

1. घोषणा/वचनबद्धता की स्वीकारोक्ति के रूप में कोष्ठक में निशान लगाएं और प्रस्तुत करें

आवेदक का हस्ताक्षर	डिजिटल हस्ताक्षर की सहायता से ई कॉम मॉड्यूल में डिजिटल रूप से प्रस्तुत किया जाए।
--------------------	----------------------------------------------------------------------------------

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 29th January, 2020

No. 58 /2015-2020

Subject: Withdrawal of MEIS for items in the Apparel and Made-ups sector (Chapter 61, 62 and 63 of ITC HS 2017) from 07.03.2019, Amendment in the para 4.95 of the Handbook of Procedures, 2015-20 and revision of the ANF 4R for Implementation of RoSCTL Scheme

F. No. 01/61/180/360/AM-19/PC-3/Part -2.— In exercise of powers conferred under paragraphs 1.03 and 3.13 (a) and (b) of the Foreign Trade Policy (2015-2020), the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments:

1. In the Appendix 3B, Table 2 of the Handbook of Procedures (HBP) applicable for MEIS, following is inserted:

“No MEIS benefits shall be available for items under chapter 61, 62 and 63 of ITC HS 2017 (apparel and made-ups sectors) for exports made with effect from 07.03.2019”.

2. The revised paragraphs 4.95 and 4.96 of the HBP are as under:

4.95 Procedure to apply for the Scheme for Rebate of State and Central Levies and Taxes (RoSCTL) and Additional Ad hoc incentive under RoSCTL

- a. The para 4.01 (c) of the FTP is about the RoSCTL. **The Gazette notifications of the Ministry of Textiles on the RoSCTL scheme and the Additional ad-hoc incentive under RoSCTL issued from time to time may be referred to.**
- b. An application for claiming rebate under RoSCTL and Additional Ad hoc incentive, shall be filed online, using digital signature, on DGFT website at <http://dgft.gov.in> with RA concerned in ANF4 R. The relevant shipping bills shall be linked with the on-line application by the exporter/ applicant online. There would be no requirement of linking e BRCs for applying for RoSCTL. A maximum of 50 shipping bills would be allowed to be attached in one single application by the exporter in the online module.
- c. **Separate online applications for claims under RoSCTL for shipping bills with Let Export date in the period 07.03.2019 to 31.12.2019 and with Let Export date on or after 01.01.2020 shall be made.**
- d. Facility of Split Scrips: Provisions of para 3.09 of the HBP shall apply mutatis mutandis.
- e. The Jurisdictional RA for application of the RoSCTL would be as per the para 3.06 (b) of the HBP. The applicants shall ensure that they are applying only to the concerned Jurisdictional RA, as per para 3.06 (b) of the Handbook of Procedures for getting the scrip and shall submit a declaration to that effect while applying for the scrip online. However, the limitation imposed in para 3.06 (a) regarding choosing a RA at the beginning of financial year and maintaining the same RA for all applications in that Financial year shall not apply.
- f. Choice of Port of Registration for RoSCTL Scrips: While making an online application
 - i. Shipments from EDI Ports and Non-EDI Ports cannot be clubbed in one application.
 - ii. The applicant can chose the Port of registration for EDI enabled ports from any one of the ports from where export is made.
 - iii. In case of exports through non-EDI port, the port of registration shall be the relevant non-EDI port of exports. Accordingly, separate application shall be filed for each non-EDI port.
- g. **For applications in the period 07.03.2019 to 31.12.2019, the DGFT online system shall electronically populate the entitlement per shipping bill including the additional ad-hoc incentive and reduce/adjust MEIS wherever already granted.**
- h. **After system based approval of the final entitlement, scrips will be issued by RAs, in a paperless mode. However, RAs shall scrutinize 2% percent of issued RoSCTL applications, under a Risk Management System (RMS), every week. The RMS cases will be randomly generated by the DGFT system online.**
- i. Registration of Scrips: Port of Registration of Scrips issued under RoSCTL would be as follows:

- i. Duty Credit Scrip (including splits) shall be issued with a single port of registration which shall be any one of the EDI ports from where export is made. In case of shipments from Non EDI ports, the Duty Credit Scrip (including splits) under RoSCTL shall be issued with a single port of registration which shall be the port of export.
- ii. Duty credit scrip needs to be registered at the port mentioned on the scrip. This is to be done prior to allowing usage of duty credit. Once registered at EDI port, scrip can be automatically used at any EDI port for import and at any manual port under Telegraphic Release Advise (TRA) procedure.
- iii. In case port of registration is a manual port, TRA shall be required for imports at any other port.
- j. Validity period and Revalidation: Duty Credit Scrip shall be valid for a period of 24 months from the date of issue and must be valid on the date on which actual debit of duty is made. Revalidation of Duty Credit Scrip shall not be permitted unless covered under paragraph 2.20(c) of HBP.
- k. **Last date of filing of application for Duty Credit Scrips: The applications for shipping bills**
 - a. **For shipping bills with LEO date from 07.03.2019 to 31.12.2019, the last date for filing online claims will be 30.06.2020.**
 - b. **For shipping bills with LEO date on or after 01.01.2020, the last date for filing online applications will be within one year from the date of LEO.**

After these deadlines, no application can be filed and the shipping bills would be time barred. There is no provision of late cut under RoSCTL.
- l. Processing of Non EDI Shipping bills at RA: In case of Non EDI shipping bills concerned RA shall verify the details entered by the exporter from the original shipping bills before grant of scrip.
- m. A duplicate scrip may be issued under the RoSCTL, under the provisions of the para 2.24 of the Handbook of Procedures 2015-20.
- n. All exporters are eligible for making a claim under the RoSCTL, except the entities/IEC which are in the Denied Entity List of the DGFT.

4.96 Recovery Mechanism

- a. The record of shipping bills and other documents related to export, is required to be maintained by the applicant for a period of 3 years from the date of issuance of scrip for post issue scrutiny and recovery purposes. Licensing Authority may call such documents in original at anytime within 3 years. In case the applicant fails to submit the original documents on demand by Licensing Authority, the applicant shall be liable to refund the rebate granted along with interest at the rate prescribed under Section 28AA of Customs Act, 1962, from the date of issuance of scrip.
 - b. Also, there can be instances, where based on the application of the exporter, amount more than the eligible amount has been issued under RoSCTL, **while adjusting for MEIS or otherwise**. In such cases, concerned RA will examine the relevant scrip's electronic records and in case, an excess claim/ excess disbursement is noted by the RA, the applicant shall refund the excess claim with interest as prescribed in paragraph 3.19 of FTP.
 - c. In case the applicant fails to refund the excess claim as stipulated above or does not respond to any communication by RA within 30 days of receipt of such communication, RA will initiate action as per FT (D&R) Act, 1992 and Rules.
 - d. The rebate allowed is subject to the receipt of sale proceeds within time allowed under the Foreign Exchange Management Act, 1999 failing which such rebate shall be deemed never to have been allowed. Action under the FT (D&R) Act, 1992 may be taken by the Regional Authorities for repayment of erroneous or excess paid RoSCTL. Further, the exporter is required to return any overpayment of rebate issued through the scrips arising from miscalculation. Where-ever recovery of such excess paid is due, interest shall also be paid by exporter at the rate of fifteen percent per annum calculated from the date of debit of the scrip till the date of repayment. In case the exporter returns the un-utilized scrips, no interest will be charged, however, penalty may be imposed under an Adjudication order on the grounds of mis-declaration or fraudulent practice.
3. The ANF 4 R is revised, and is at Annexure to this Public Notice.
 4. The following para is added in the chapter 3 of HBP:

“3.01 (I) The excess/undue claims paid to the exporters under MEIS, for exports with Let Export date between the period 07.03.2019 to 31.12.2019, relating to apparel and made-ups (chapter 61, 62 and 63) will be suitably adjusted against RoSCTL and recoveries made, wherever due.”

Effect of this Public Notice: Based on notifications for Scheme for Rebate of State and Central Taxes and Levies (RoSTCL) by the Ministry of Textiles procedure in paragraphs 4.95 and 4.96 has been revised and Aayat Niryat Form (ANF 4R) has been revised. On account of introduction of RoSCTL, MEIS for items of the apparel and made-ups sector (chapter 61, 62 and 63) for exports made w.e.f. 07.03.2019 stands withdrawn.

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade & Ex-Officio Addl. Secy.

Annexure to the Public Notice No. Dated January, 2020

ANF- 4 R

Application Form to Apply for the Scheme for Rebate of State and Central Taxes and Levies (RoSCTL) as notified in the para 4.95 and 4.96 of the Handbook of Procedures 2015-20)

Guidelines for Applicants

1. Kindly refer to Paras 4.95 and 4.96 of the HBP 2015-20 and Gazette Notifications published by the Ministry of Textiles on the ROSCTL, and declarations in the ANF 4R before applying.
2. Please note that based on Let Export date separate applications are required to be filed for shipping bills in the period 07.03.2019 to 31.12.2019 and for shipping bills from 01.01.2020.
3. The online E com module would auto-calculate the RoSCTL entitlement based on the rates/caps/ additional ad-hoc incentive notified by the Ministry of Textiles' Gazette Notifications as amended from time to time, after suitably adjusting for MEIS already issued for shipping bills in the period 07.03.2019 to 31.12.2019
4. Applicant is required to select/feed the details of one shipping bill at a time. A maximum of 50 shipping bills can be selected for rebate in one application

Part A

1.	Applicant Details:										
i	IEC No.										
ii	Name of the IEC										
iii	Address										
iv	Telephone No.										
v	Valid / Active Email ID										

Part B

2. Application Details:

- i. Export Licensing Year [pl. specify the year in which export has been made, based on Let export date (Para 9.12 of HBP)]:
- ii. Date of filing of Application:
- iii. Port of Export for this Application:

3. Shipping Bill Details: The Eligible Shipping Bills would be available in the shipping bill repository online. The Exporters are required to select the shipping bills and build their application. There is no requirement for filling the details for EDI shipping bills.

4. Number of Split Certificates required (in multiples of Rs 5 lakhs each):

5. Port of Registration for the purpose of imports. (The port of registration shall be one of the ports from which exports have taken place)

6. Declaration / Undertaking

1	<p>I/We hereby certify that :</p> <p>A. the entity for whom the application has been made have not been penalized/ have been penalized (choose as applicable) under any of the following Acts (as amended from time to time):</p> <p>(i) The Customs Act, 1962,</p> <p>(ii) The Central Excise Act 1944,</p> <p>(iii) Foreign Trade (Development & Regulation) Act 1992,</p> <p>(iv) The Foreign Exchange Management Act, 1999; and</p> <p>(v) The Conservation of Foreign Exchange, Prevention of Smuggling Activities Act, 1974</p> <p>B. none of the Directors / Partners / Proprietor / Karta / Trustees of the company /firm /HUF/Trust, (as the case may be), is/are a Director(s) / Partner(s) / Proprietor / Karta / Trustee in any other Company/ firm / entity which is on the Denied Entity List (DEL) of DGFT;</p> <p>C. neither the Registered Office of the company / Head Office of the firm / nor any of its Branch Office(s)/ Unit(s)/ Division(s) has been declared a defaulter and has otherwise been made ineligible for undertaking import / export under any of the provisions of the Policy;</p>
2	I/We undertake to abide by the provisions of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, as amended from time to time, the Rules and Orders framed there under, the Foreign Trade Policy, the Handbook of Procedures
3	I/We hereby certify that that particulars and statements made in this application are true and correct and nothing has been concealed or held therefrom. I/We fully understand that any information furnished in the application if found incorrect or false will render me/us liable for any penal action or other consequences as may be prescribed in law or otherwise warranted.
4	I have gone through the para 3.06 (b) of the HBP 2015-20 and am submitting this instant ROSCTL application to my jurisdictional Regional Authority as per Appendix 1A
5	I hereby certify that I am authorized to verify and sign this declaration as per Paragraph 9.06 of the Foreign Trade Policy.
6	I hereby declare that I have read the provisions of the para 4.96 of the HBP 2015-20 regarding the Recovery Mechanism and I declare that none of the consignment in respect of which claim is filed in this application has been subsequently returned. In case it is returned in future, I undertake to refund the rebate granted with interest rates as prescribed under section 28AA of Customs Act, 1962. I also declare that I have not claimed and shall not claim credit/rebate/refund/re-imbursement of the specified levies and taxes under any other mechanism from State Government/ Central Government.
7	I hereby declare that this application does not contain any exports in contravention provisions as specified in the Ministry of Textiles Gazette Notifications on ROSCTL in this regard.
8	I agree that RoSCTL claim against the shipping bills in this application will be granted after making suitable adjustments for MEIS benefits already taken on these export shipments, wherever applicable, as per the Ministry of Textiles Notification dated 14.01.2020, F. No. 14/26/2016-IT/VOL II available at egazette.nic for exports shipments between 07.03.2019 and 31.07.2019.
9	In case, any undue/ excess RoSCTL amount is granted to me, I undertake to refund the amount in cash with interest at the rate prescribed under section 28AA of Customs Act, 1962, from the date of such scrip as and when advised by the RA/ suo-motu . In case I am not able to refund the excess / undue amount disbursed under RoSCTL or am not able to submit adequate documentary evidence substantiating RoSCTL claims before the concerned authorities/RA , I know that I may be liable to penal action under FT(D&R) Act.

1. Tick the box as acceptance of declaration/ undertaking and submit

Signature of the Applicant	To be Digitally Submitted in the E com module with the help of a Digital Signature
----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------